

हाक ध्यय की पूर्व-अवधि की  
बिना हाक द्वारा भेजे जाने के  
लिये अनुमत. अनुमति-पत्र  
क. भोपाल-505/इ.पू. पी.



[पंजी क्रमांक. भोपाल विवीजन  
122](एम. पा.)

# मध्य प्रदेश राजपत्र

## (असाधारण)

### अधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 411]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 30 अक्टूबर 1982— आश्विन 8: शके 1904

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 1982

क. 2005-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्य प्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 30 अक्टूबर 1982 का राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्व-साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वि. मा. आगवण, उपसचिव.

मध्य प्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३७ सन् १९८२.

मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अधिनियम, १९८२।

विषय-सूची.

धाराएं:

अध्याय १—प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम और विस्तार.
२. परिभाषाएं.

अध्याय २—निगम की स्थापना, उसकी पूंजी तथा उसका प्रबंध.

३. मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना तथा उसका निगमन.
४. निगम का प्रधान कार्यालय.
५. निगम की पूंजी.

अध्याय ३—निगम का प्रबंध.

६. प्रबन्ध.
७. बोर्ड का गठन.
८. निगम का निदेशक होने के लिए निरहंता.

९. नामनिर्दिष्ट निदेशकों द्वारा पद का रिक्त किया जाना।
१०. प्रबन्ध निदेशक.
११. प्रबन्ध निदेशक के पद में आकस्मिक रिक्तियां.
१२. निदेशकों का पारिश्रमिक.
१३. बोर्ड का संयोजन.
१४. बोर्ड की समिति।
१५. बोर्ड द्वारा उसका सामाजिक सदस्य कतिपय मामलों में भाग नहीं लेगा या उनमें मत नहीं देगा.
१६. प्रबन्ध निदेशक नियुक्ति प्राधिकार होगा.
१७. सरकारी विभाग से निगम को स्थानान्तरित किये गये कर्मचारियों की सेवा की शर्तें.

अध्याय ४—निगम का कामकाज तथा वे उधार जिन्हें निगम ले सकेगा.

१८. वह कामकाज जो निगम कर सकेगा.
१९. निगम की उधार लेने की शक्ति.
२०. निधियों के अन्य स्रोत.

अध्याय ५—परियोजनाओं का निष्पन्न.

१९. संकल्पों का निष्पादन.

अध्याय ६—वित्तीय प्राक्कलन, निधियां, लेख तथा संपरीक्षा.

२२. क्रियाकलापों का कार्यक्रम तथा वित्तीय प्राक्कलन का प्रस्तुत किया जाना.
२३. निगम की निधि.
२४. निगम के तुलनपत्रों आदि का तैयार किया जाना.
२५. अधिशेष लाभ का आवंटन.
२६. लेख तथा संपरीक्षा.
२७. विवरणियां.

अध्याय ७—प्रकीर्ण.

२८. राज्य सरकार की निदेश देने की शक्ति.
२९. सरकारी कर्मचारियों के निगम को स्थानान्तरण.
३०. निगम का समापन.
३१. निदेशकों की क्षतिपूर्ति.
३२. निदेशकों की नियुक्ति में वृद्धियां होने के कारण कार्यों आदि का अविधिमाम्य होना.
३३. निगम के कर्मचारी-वृद्ध लोक सेवक होंगे.
३४. इस अधिनियम के अधीन की नई कार्यवाही का संरक्षण.
३५. विश्वस्तता तथा शोपनीयता की घोषणा.
३६. शक्तियों व प्रत्यायाजन.
३७. नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति.
३८. विनियम बनाने की निगम की शक्ति.
३९. निरसन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३७ सन् १९८२.

मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अधिनियम, १९८२.

[दिनांक ३० अक्टूबर १९८२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ३० अक्टूबर १९८२ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

राज्य के पशुधन एवं कुक्कुट संसाधनों का विकास करने तथा उनके वनानिक प्रबन्ध के लिए व्यवस्था करने की दृष्टि से, परियोजनाओं के निष्पादन के लिए एक निगम की स्थापना करने तथा उससे संसक्त विषयों के लिए उपबन्ध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तैत्तीष्वे वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय १—प्रारम्भिक.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अधिनियम १९८२ है. संक्षिप्त नाम और विस्तार.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.

२. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएँ.

(क) "बैंक" से अभिप्रेत है—

(एक) बैंककारी विनियमन अधिनियम, १९४६ (१९४६ का सं. १०) में यथापरिभाषित कोई बैंककारी कम्पनी;

(दो) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ (१९३४ का सं. २) में यथापरिभाषित कोई अनुसूचित बैंक;

(तीन) मध्यप्रदेश को-ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) में यथापरिभाषित कोई वित्तदायी बैंक;

(ख) "बोर्ड" से अभिप्रेत है धारा ७ के अधीन गठित किया गया निगम का निदेशक बोर्ड;

(ग) "वित्तदायी संस्था" से अभिप्रेत है भारत में स्थापित कोई कानूनी निगम या अन्य निगमित निकाय जिसके उद्देश्यों में से एक उद्देश्य भारत में कृषि का वित्तपोषण करना हो और जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वित्तदायी संस्था के रूप में अधिसूचित करे;

(घ) "भूमि" का वह अर्थ होगा जो मध्यप्रदेश लेण्ड रेवेन्यू कोड, १९५६ (क्रमांक २० सन् १९५६) में उस अभिव्यक्ति के लिए किया गया है;

(ङ) "निगम" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम;

(च) "परियोजना" से अभिप्रेत है धारा २२ के अधीन अनुमोदित पशुधन एवं कुक्कुट विकास की कोई परियोजना या स्कीम;

- (घ) "विनियम" से अभिप्रेत है निगम द्वारा धारा ३८ के अधीन बनाए गए विनियम;  
 (ज) "वर्ष" से अभिप्रेत है प्रतिवर्ष १ जुलाई से प्रारंभ होने वाला तथा ३० जून को समाप्त होने वाली कालावधि.

अध्याय २—निगम की स्थापना, उसकी पूंजी तथा उसका प्रबन्ध.

मध्यप्रदेश राज्य पशु-  
 धन एवं कुक्कुट  
 विकास निगम की  
 स्थापना तथा उसका  
 निगमन.

३. (१) ऐसी तारीख से, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक निगम की स्थापना की जायगी जो मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के नाम से जाना जायगा.

(२) निगम पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसका शास्वत् उत्तराधिकार होगा तथा जिसकी सामान्य मुद्रा होगी और जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जंगम तथा स्थवर दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और उसका व्ययन करने की, और संविदा करने की शक्ति होगी और जो उक्त नाम से वाद चलायेगा तथा जिसके विरुद्ध उक्त नाम से वाद चलाया जायगा.

निगम का प्रधान  
 कार्यालय.

४. निगम का प्रधान कार्यालय भोपाल में होगा.

निगम की पूंजी,

५. (१) निगम की प्राधिकृत पूंजी शीरो करोड़ रुपए से अनधिक ऐसी राशि की होगी जोकि राज्य सरकार, समय-समय पर नियत करे.

(२) राज्य सरकार को यह शक्ति होगी कि वह उस राशि के संबंध में, जिसका कि प्रावधान राज्य सरकार द्वारा निगम की पूंजी के रूप में किया जाय, ऐसे निवन्धन तथा शर्तें अधिरोपित करे जैसी कि वह ठीक समझे.

अध्याय ३—निगम का प्रबन्ध.

प्रबन्ध.

६. (१) निगम के कार्यकाल तथा कारबार का साधारण अधीक्षण, निदेशन तथा प्रबन्ध निदेशक-बोर्ड में निहित होगा जो ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा तथा ऐसे समस्त कार्य और बातें कर सकेगा जिनका कि प्रयोग निगम द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया जा सकता है या जो निगम द्वारा इस अधिनियम के अधीन की जा सकती हैं.

(२) निदेशक-बोर्ड, अपने कृत्यों का पालन करने में, लोकहित का ध्यान रखते हुए, कारबार संबंधी सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेगा और नीति विषयक प्रश्नों पर ऐसे निर्देशों से मार्गदर्शित होगा जो उसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिए जायें.

बोर्ड का गठन.

७. (१) निगम का निदेशक-बोर्ड, अध्यक्ष, जो कि राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायगा, तथा निम्नलिखित अन्य निदेशकों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

- (एक) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग, और यदि कोई सचिव न हो तो उस विभाग का विशेष सचिव, जो उपाध्यक्ष होगा;
- (दो) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग या उसका नाम निर्देशिती जो उप सचिव की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो;
- (तीन) संचालक, पशु-चिकित्सा सेवाएं, मध्यप्रदेश;
- (चार) रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियां, मध्यप्रदेश;
- (पांच) धारा १० के अधीन नियुक्त किया जाने वाला प्रबन्ध निदेशक;
- (छ) बैंकों तथा वित्तदायी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक निदेशक, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायगा;
- (सात) पशुधन एवं कुक्कुट विकास के बारे में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाला एक निदेशक, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायगा;
- (आठ) पशुधन एवं कुक्कुट उत्पादन तथा विपणन का व्यावहारिक अनुभव रखने वाले दो निदेशक, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जायेंगे;



(नौ) पशुधन एवं कुक्कुट विषयक व्यावहारिक अनुभव रखने वाला अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक प्रतिनिधि, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(दस) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि, जो कुलपति की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा.

(२) अध्यक्ष या कोई नामनिर्दिष्ट निदेशक उसे नामनिर्दिष्ट करने वाले प्राधिकारी के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा किन्तु उसके पद की अवधि उसके नामनिर्देशन की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष से अधिक की नहीं होगी. तथापि, अध्यक्ष या कोई नामनिर्दिष्ट निदेशक, क्रमशः राज्य सरकार को तथा बोर्ड के अध्यक्ष को स्वहस्ताक्षरित पत्र भेजकर, अपना पद किसी भी समय त्याग सकेगा, और त्यागपत्र उसके प्राप्त होने की तारीख से प्रभावी होगा:

(३) अध्यक्ष या किसी नामनिर्दिष्ट निदेशक की मृत्यु हो जाने, उसके द्वारा पद त्याग कर दिये जाने, उसके निरहित हो जाने या उसे हटाये जाने की दशा में, वह रिक्त नामनिर्देशन द्वारा यथासंभव शीघ्र भरी जाएगी.

८. (१) कोई भी व्यक्ति निगम के निदेशक के रूप में नामनिर्दिष्ट किये जाने या नियुक्त किये जाने के लिये तथा निगम का निदेशक होने के लिये निरहित होगा—

(क) यदि वह न्यायनिर्णीत दिवालिया है या किसी भी समय न्यायनिर्णीत दिवालिया रहा है या उसने अपने ऋणों का भुगतान निरन्तरित कर दिया है या अपने जेजदारों के साथ प्रामाण्य कर लिया है; या

(ख) यदि वह विवृत-चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा होना घोषित कर दिया जाता है; या

(ग) यदि उसे पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, १९६० (१९६० का सं. ५६), सेन्ट्रल प्राविन्सेस एण्ड बरार स्लटर ऑफ एनीमल्स एक्ट, १९१५ (क्रमांक ४ सन् १९१५) या मध्यप्रदेश पशु परिरक्षण अधिनियम, १९५६ (क्रमांक १८ सन् १९५६) के अधीन किसी अपराध का सिद्धोप ठहराया जाता है या ठहराया जा चुका है; या

(घ) यदि उसे सरकार की या किसी ऐसे निगम की, जिस पर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का स्वामित्व या नियंत्रण है, सेवा से हटा दिया जाता है या पदच्युत कर दिया जाता है; या

(ङ) यदि वह कि तो ऐसी रीति में कार्य करता है जो निगम के हित के प्रतिकूल है या किसी ऐसे निकाय, संस्था या संगठन में कोई हित रखता है जिसके क्रियाकलाप निगम के हित के प्रतिकूल हैं.

(२) यदि निगम का कोई निदेशक उपधारा (१) में वर्णित निरर्हताओं में से किसी भी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है तो वह राज्य सरकार द्वारा जारी की गई इस आशय की अधिसूचना की तारीख से निगम का निदेशक नहीं रहेगा.

९. (१) यदि कोई नामनिर्दिष्ट निदेशक—

(क) धारा ८ में वर्णित निरर्हताओं में से किसी निरर्हता के अधधीन हो जाता है; या

(ख) बोर्ड की इजाजत के बिना, उसके तीन से अधिक क्रमवर्ती सम्मिलनों में ऐसे कारण के बिना अनुपस्थित रहता है जो उसकी अनुपस्थिति की माफी के लिये, राज्य सरकार की राय में, पर्याप्त है,

नामनिर्दिष्ट निदेशकों द्वारा पद का रिक्त किया जाना.

तो राज्य सरकार यह घोषित कर सकेगी कि उक्त निदेशक के संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने इस आशय की अधिसूचना की तारीख से अपना पद रिक्त कर दिया है और तदुपरि उसका स्थान रिक्त हो जाएगा.

(२) कोई ऐसा निदेशक, जिसका पद उपधारा (१) के अधीन रिक्त घोषित कर दिया गया हो, बोर्ड में निदेशक के रूप में पुनः नामनिर्दिष्ट किया जाने के लिये या निगम में किसी भी हैसियत में नियोजित किया जाने के लिये पात्र नहीं होगा.

१०. (१) प्रबंध निदेशक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी और वह—

प्रबंध निदेशक.

(एक) निगम का पूर्णकालिक अधिकारी होगा;

(दो) ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो कि बोर्ड उसे प्रत्यायोजित करे या सौंपे;

(तीन) ऐसा वेतन तथा भत्ते प्राप्त करेगा और सेवा के ऐसे निवन्धनों तथा शर्तों द्वारा शासित होगा कि निगम, राज्य सरकार के अनुमोदन से, अवधारित करे.

परन्तु प्रथम प्रबंध निदेशक ऐसा वेतन तथा भत्ते प्राप्त करेगा और सेवा के ऐसे निबंधनों तथा शर्तों द्वारा शासित होगा जैसी कि राज्य सरकार अवधारित करे.

(२) राज्य सरकार, कोई कारण बताए बिना, प्रबंध निदेशक को किसी भी समय पद से हटा सकेगी.

प्रबंध निदेशक के पद में आकस्मिक रिक्तियां.

११. यदि प्रबंध निदेशक, अंग-शैथिल्य के कारण या अन्यथा, अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाता है या छुट्टी पर होने के कारण या अन्यथा, ऐसी परिस्थितियों में जिनमें उसके पद की रिक्ति अन्तर्वर्तित नहीं है, अनुपस्थित रहता है तो राज्य सरकार उसकी अनुपस्थिति के दौरान उसके स्थान पर कार्य करने के लिये किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी.

निदेशक का पारिश्रमिक.

१२. धारा १० में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, निदेशकों को बोर्ड के या उसकी समितियों में से किसी समिति के सम्मिलन में हाजिर होने के लिये तथा निगम का कोई अन्य कार्य करने के लिये ऐसी फीस तथा भत्तों का संदाय किया जाएगा जिनका कि विनियमों द्वारा उपबंध किया जाए :

परन्तु अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक को या किसी अन्य निदेशक को, जो राज्य सरकार का या केन्द्रीय सरकार का मंत्री या पदाधिकारी है, इस धारा के अधीन कोई फीस देय नहीं होगी.

बोर्ड के सम्मिलन.

१३. (१) बोर्ड ऐसे समयों पर तथा ऐसे स्थानों पर सम्मिलन करेगा और अपने सम्मिलनों में कामकाज के संपादन के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुपालन करेगा जो विनियमों द्वारा उपबंधित किए जाएं:

परन्तु बोर्ड प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार सम्मिलन करेगा.

(२) बोर्ड का अध्यक्ष या, उसकी अनुपस्थिति में कोई अन्य ऐसा निदेशक, जो सम्मिलन में उपस्थित निदेशकों द्वारा चुना गया हो, सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा.

(३) बोर्ड के किसी सम्मिलन के समक्ष आने वाले समस्त मामले, उपस्थित तथा मत देने वाले निदेशकों के बहुमत से विनिश्चित किए जाएंगे और मतों के बराबर-बराबर होने की दशा में, सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा.

(४) यदि बोर्ड किसी विशिष्ट मामले पर किसी व्यक्ति की सलाह या राय लेना आवश्यक समझता है, तो बोर्ड ऐसे व्यक्ति को बोर्ड के किसी सम्मिलन में हाजिर होने के लिये आमंत्रित कर सकेगा. ऐसे आमंत्रित व्यक्ति को ऐसे सम्मिलन में किसी भी चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उसे ऐसे सम्मिलन में मत देने का अधिकार नहीं होगा.

बोर्ड की समितियां.

१४. (१) बोर्ड इतने निदेशकों से, जितने कि विनियमों द्वारा उपबंधित किए जाएं, मिलकर बनने वाली एक या अधिक कार्यकारिणी समितियां इस हेतु से गठित कर सकेगा कि वे ऐसे कृत्यों का निर्वहन करें जो उन्हें बोर्ड द्वारा प्रत्या-योजित किए जाएं.

(२) बोर्ड, निगम के क्रियाकलापों से संबंधित ऐसे प्रयोजनों के लिये, ऐसी समितियां, जैसा कि वह विनिश्चित करे, गठित कर सकेगा जो या तो पूर्णतः निदेशकों से या पूर्णतः अन्य व्यक्तियों से, जैसा कि वह ठीक समझे, मिलकर बनेंगी.

(३) किसी समिति के ऐसे सदस्यों को, जो निगम के निदेशकों से भिन्न हों, उसके सम्मिलन में हाजिर होने के लिये तथा निगम का कोई अन्य कार्य करने के लिये निगम द्वारा ऐसी फीस और/या भत्तों का संदाय किया जाएगा जिनका कि विनियमों द्वारा उपबंध किया जाए.

बोर्ड का या उसकी समिति का सदस्य कतिपय मामलों में भाग नहीं लेगा या उनमें मत नहीं देगा.

१५. निगम का कोई ऐसा निदेशक या किसी समिति का कोई ऐसा सदस्य, जो बोर्ड के या उसकी किसी समिति के सम्मिलन में विचारार्थ आने वाले किसी मामले में धन संबंधी कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित रखता है, अपने हित की प्रकृति को ऐसे सम्मिलन में प्रकट करेगा और ऐसा प्रकटन यथास्थिति बोर्ड या समिति के कार्यवृत्त में अभिलिखित किया जाएगा; और ऐसा निदेशक या सदस्य उस मामले के संबंध में बोर्ड या समिति द्वारा किए जाने वाले किसी विचार-विमर्श या विनिश्चय में, ऐसा स्पष्टीकरण, जिसकी उससे अपेक्षा की जाय, देने के सिवाय, कोई भाग नहीं लेगा.

प्रबंध निदेशक नियुक्ति प्राधिकारी होगा.

१६. निगम की ओर से कार्य करने वाला प्रबंध निदेशक नियुक्ति प्राधिकार समझा जायगा और वह निगम द्वारा नियोजित समस्त कर्मचारीवृत्त के बारे में ऐसे प्राधिकारी की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा प्रबंध निदेशक द्वारा इस संबंध में किए गए आदेश के विरुद्ध अपील बोर्ड के अध्यक्ष को ऐसी रीती में होगी जो विनियमों द्वारा उपबंधित की जाए.

१७. (१) धारा २६ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई ऐसा पदधारी, जो निगम की प्रार्थना पर राज्य सरकार द्वारा अपने किसी विभाग से निगम को स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से स्थानान्तरित किया गया है, उपदान (ग्रेज्युटी) संबंधी, पेंशनिके फायदों तथा किन्हीं अन्य फायदों संबंधी समस्त ऐसे विशेषाधिकारों का उपभोग करेगा जिनका कि वह पदधारी राज्य सरकार में के अपने मूल विभाग में सेवा करते रहने की दशा में हकदार होता।

सरकारी विभाग से निगम को स्थानान्तरित किये गये कर्मचारी की सेवा की शर्तें.

(२) उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट किया गया कोई पदधारी, निगम में नियोजित रहने की अवधि के दौरान निगम के अनुशासनिक नियंत्रण के अधीन रहेगा।

अध्याय ४—निगम का कामकाज तथा वे उधार जिन्हें निगम ले सकेगा.

१८. निगम का मुख्य कामकाज होगा पशुधन और पशुधन उत्पादों (दुग्ध और दुग्ध उत्पादों को छोड़कर) का तथा कुक्कुट और कुक्कुट उत्पादों का उत्पादन, उपापन (प्रोक्वोरमेंट), संग्रहण, प्रालन-पोषण और विपणन करना और पशुधन तथा कुक्कुट का संरक्षण, प्रबंध और विकास करना जिससे कि राज्य में पशुधन तथा कुक्कुट उत्पादन में सुधार हो सके, उसकी सहायता हो सके और उसमें वृद्धि हो सके।

वह कामकाज जो निगम कर सकेगा.

१९. (१) निगम, निधियां जुटाने के प्रयोजन के लिये, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ब्याज बन्धपत्र और डिबेन्चर पुरोधृत कर सकेगा और बेच सकेगा :

निगम की उधार लेने की शक्ति.

परन्तु पुरोधृत और परादेय बन्धपत्रों और डिबेन्चरों की तथा निगम के अन्य उधारों की कुल रकम, राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना किसी भी समय उस पूंजी की रकम के चार गुने से अधिक नहीं होगी जिसका कि उपबंध राज्य सरकार द्वारा धारा ५ के अधीन किया गया हो।

(२) निगम, इस अधिनियम के अधीन के अपने कृत्यों का निष्पादन करने के प्रयोजन के लिये,—

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से और किसी ऐसे अन्य प्राधिकरण या संगठन या संस्था से, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की गई हो, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर धन उधार ले सकेगा जैसी कि करार पाई जाएं;

(ख) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार से या किसी अनुसूचित बैंक या किसी व्यक्ति से ऐसे निक्षेप, जो उस तारीख से, जिसको कि ऐसे निक्षेप किये जाएं, ऐसी कालावधि का जो बारह मास से कम की नहीं होगी, अवसान होने के पश्चात् प्रतिसंदेह होंगे, ऐसे निबन्धनों पर प्रतिगृहीत कर सकेगा जिन्हें कि निगम, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, नियत करे.

(३) राज्य सरकार निगम के उन बंधपत्रों तथा डिबेन्चरों को, जो उपधारा (१) के अधीन पुरोधृत किए गए हों और निगम द्वारा उपधारा (२) के खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन लिए गए उधार तथा निक्षेपों की, मूलधन का प्रतिसंदाय किये जाने के बारे में तथा ब्याज का संदाय ऐसी दर से किए जाने के बारे में प्रत्याभूत कर सकेगी जो बंधपत्रों या डिबेन्चरों के पुरोधृत किए जाने के समय निगम के निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा नियत की जाए.

२०. (१) निगम अपनी सेवाओं के लिये पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत संकर्मों की वह लागत आती है जो निगम द्वारा इस अधिनियम के अधीन उपगत की गई हो, प्राप्त कर सकेगा तथा राज्य सरकार से या किसी व्यक्ति से दान, अनुदान, सहायिकी, संदाय या कोई उपकृतियां (बेनीफेक्सेस) प्रतिगृहीत कर सकेगा।

निधि के अन्य स्रोत.

(२) राज्य सरकार निगम के उपयोग के लिए निगम को भवन, भूमि, मशीनरी या कोई अन्य जंगम या स्थावर संपत्ति भी ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर अन्तरित कर सकेगी जो राज्य सरकार ठीक समझे.

अध्याय ५—परियोजनाओं का निष्पादन.

२१. निगम संकर्मों को स्वयं या किसी अन्य अभिकरण की मार्फत निष्पादित कर सकेगा.

संकर्मों का निष्पादन.

अध्याय ६—वित्तीय प्राक्कलन, निधियां, लेखे तथा संपरीक्षा.

२२. (१) निगम, प्रत्येक वर्ष के संबंध में, अपने क्रियाकलापों के कार्यक्रम का विवरण तथा साथ ही वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसमें उस वर्ष के लिये निगम की प्राक्कलित प्राप्तियां तथा व्यय विस्तारपूर्वक दर्शाये जायेंगे, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा.

क्रियाकलापों का कार्यक्रम तथा वित्तीय प्राक्कलन का प्रस्तुत किया जाना.

(२) निगम उपधारा (१) में निर्दिष्ट किये गए विवरण तथा प्राक्कलन को राज्य सरकार के अनुमोदन से पुनरीक्षित या उपान्तरित कर सकेगा.



(३) निगम आगामी वर्ष के दौरान निष्पादित किए जाने वाले कार्यक्रम तथा विभिन्न क्रियाकलापों संबंधी परियोजना के, ब्यौरे राज्य सरकार को प्रतिवर्ष प्रस्तुत करेगा।

(४) राज्य सरकार या तो परियोजना को अनुमोदित कर सकेगी या उसका अनुमोदन ऐसे उपान्तरणों के साथ कर सकेगी जैसे कि वह आवश्यक समझे अथवा उस परियोजना को उपान्तरित किए जाने हेतु या ऐसे निदेशों के अनुसार; जैसे कि राज्य सरकार समुचित समझे, नई परियोजना तैयार किए जाने के हेतु वह परियोजना निगम को लौटा सकेगी।

निगम की निधि.

२३. (१) निगम की अपनी स्वयं की निधि होगी और वह उसे बनाए रखेगा, तथा निगम की समस्त प्राप्तियां उसमें जमा की जाएंगी तथा निगम द्वारा समस्त संदाय उसमें से किए जाएंगे।

(२) निगम की निधि का उपयोग निगम द्वारा अपने समस्त प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति करने के लिये तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये किया जाएगा।

(३) निगम ऐसी राशियां, जिनकी कि उसे अपनी संक्रियाओं के लिए आवश्यकता हो, किसी बैंक में निक्षिप्त कर सकेगा और अधिशेष ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जाए, विनिहित किया जा सकेगा।

निगम के तुलन-पत्रों आदि का तैयार किया जाना.

२४. (१) बोर्ड निगम की बहियों तथा लेखाओं को, जैसे कि वे प्रतिवर्ष तीस जून को हों, संतुलित करवाएगा तथा बंद करवाएगा।

(२) निगम का तुलन-पत्र तथा लेखे ऐसी रीति में तैयार किए जाएंगे तथा बनाए रखे जायेंगे जो विनियमों द्वारा विहित की जाए।

अधिशेष लाभ का आवंटन.

२५. (१) निगम एक अरक्षित निधि स्थापित करेगा जिसमें उसके वार्षिक शुद्ध लाभों का ऐसा भाग जिसे निगम ठीक समझे, प्रतिवर्ष जमा किया जाएगा।

(२) ऐसी अरक्षित निधि के लिए तथा डबल और शंकास्पद ऋणों के लिये और समस्त ऐसे अन्य विषयों के लिये जिनके लिए कंपनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का सं. १) के अधीन रजिस्ट्रीकृत तथा निगमित कंपनी द्वारा प्रायिक रूप से उपबंध किया जाता है, उपबंध करने के पश्चात् निगम के वार्षिक शुद्ध लाभों के अधिशेष का संदाय राज्य सरकार को किया जाएगा।

लेखे तथा संपरीक्षा.

२६. (१) निगम, उचित लेखा बहियां तथा ऐसी अन्य बहियां जो नियमों द्वारा अपेक्षित हों, रखवाएगा तथा लेखाओं का वार्षिक विवरण विहित रीति में तैयार करेगा।

(२) निगम अपने लेखाओं की संपरीक्षा प्रतिवर्ष ऐसे व्यक्ति द्वारा करवाएगा जैसा कि राज्य सरकार निदेशित करे।

(३) जैसे ही निगम के लेखाओं की संपरीक्षा हो जाती है, निगम उनकी एक प्रति, उनके संबंध में संपरीक्षक की रिपोर्ट की एक प्रति के साथ, राज्य सरकार को भेजेगा और लेखाओं को विहित रीति में प्रकाशित करवाएगा और उनकी प्रतियां युक्तियुक्त कीमत पर विक्रय के लिये रखेगा।

(४) निगम ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो राज्य सरकार, संपरीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करने के पश्चात् जारी करना ठीक समझे।

विवरणियां

२७. (१) निगम राज्य सरकार को समय-समय पर ऐसी विवरणियां देगा जिनकी कि राज्य सरकार अपेक्षा करें।

(२) निगम, राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष के संबंध में तुलनपत्र की, जैसा कि वह उस वर्ष की समाप्ति के समय हो एक प्रति तथा उसके साथ ही उस वर्ष का लाभ और हानि लेखा तथा निगम के कार्यक्रम संबंधी रिपोर्ट, जिसमें उस वर्ष के दौरान की उसकी नीति तथा कार्यक्रम सम्मिलित होंगा, उस तारीख से, जिसको कि निगम के वार्षिक लेखे बन्द किये जाते हैं, तीन मास की कालावधि के भीतर देगा।

(३) राज्य सरकार, ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र उस रिपोर्ट को तथा धारा २६ के अधीन प्राप्त संपरीक्षा रिपोर्ट को विधान सभा के पटल पर रखवाएगी।

#### अध्याय ७—प्रकीर्ण.

राज्य सरकार की निर्देश देने की शक्ति.

२८. (१) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने में, निगम नीति-विषयक ऐसे मामलों में जिनमें लोकहित अन्तर्गस्त हो, ऐसे निदेशों से मार्गदर्शित होगा जैसे कि राज्य सरकार उसे लिखित में दे, और यदि कोई ऐसा प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या वह निदेश नीति-विषयक किसी ऐसे मामले से संबंधित है, जिसमें लोकहित अन्तर्गस्त है, तो उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

(२) जहाँ निगम उपधारा (१) के अधीन दिए गए राज्य सरकार के निदेशों को कार्यान्वित करने के परिणामस्वरूप अत्यन्तः कोई हानि उत्पन्न करता है, वहाँ उस हानि की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

२६. (१) निगम की स्थापना हो जाने पर तथा उसके पश्चात् राज्य सरकार समय-समय पर, यह निदेश दे सकेगी कि राज्य सरकार के विद्यमान अधिकारियों तथा सेवकों में से ऐसे अधिकारियों तथा सेवकों की, जो उसकी राय में उसकी आवश्यकता से अधिक हो गए हैं, सेवाएं ऐसी तारीख से, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं (जो इस धारा में इसके पश्चात् नियत तारीख के नाम से निर्दिष्ट है), समाप्त हो जाएंगी और उसके पद उत्सादित हो जाएंगे, और वे उस तारीख को (जो भिन्न-भिन्न अधिकारियों तथा सेवकों के लिये भिन्न-भिन्न हो सकेंगी) निगम के अधिकारी या सेवक हो जाएंगे।

सरकारी कर्मचारियों का निगम को स्थानान्तरण..

(२) राज्य सरकार का ऐसा प्रत्येक स्थायी या अस्थायी कर्मचारी, जिसके संबंध में उपधारा (१) के अधीन निदेश जारी किया जाता है, नियत तारीख को तथा नियत तारीख से किसी ऐसे स्थायी या अस्थायी पद पर, जो नियत तारीख से निगम की स्थापना में सृजित हो जाएगा, नियम का यथास्थिति स्थायी या अस्थायी कर्मचारी हो जाएगा।

(३) इस प्रकार स्थानान्तरित किया गया कोई अधिकारी या सेवक, निगम के अधीन पद उसी अवधि के लिए, उसी पारिश्रमिक पर तथा सेवा की उन्हीं अन्य शर्तों पर और पेंशन, उपदान (ग्रेजुटी), भविष्य निधि तथा अन्य बातों के संबंध में उन्हीं अधिकारों तथा विशेषाधिकारों सहित धारण करेगा जो इस अधिनियम के प्रवृत्त न होने की दशा में उसे नियत तारीख को अनुज्ञेय हुए होते। राज्य सरकार के अधीन उसके द्वारा की गई कोई सेवा निगम के अधीन की गई सेवा समझी जाएगी। वह निगम के अधीन उस समय तक सेवा में बना रहेगा जब तक कि उसका नियोजन सम्यक् रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता या जब तक कि उसका पारिश्रमिक या सेवा-शर्त निगम द्वारा उस विधि के अनुसरण में, जो तत्समय उसकी सेवा-शर्तों को शासित करती हों, सम्यक् रूप से पुनरीक्षित या परिवर्तित नहीं कर दी जाती:

परन्तु किसी ऐसे अधिकारी या सेवक के मामले में नियत तारीख के ठीक पूर्व लागू सेवा-शर्तों में कोई ऐसा फेरफार, जो उसके लिए अहितकर हो, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही किया जायगा अन्यथा नहीं।

(४) उपधारा (१) में निर्दिष्ट कर्मचारियों के नाम जो धनराशियां, उनके लिए गठित की गई किसी पेंशन, भविष्य निधि, उपदान या वैसी ही निधियों में जमा हों, वे नियत तारीख तक के लिये शीघ्र संचित ब्याज सहित तथा ऐसी निधियों से संबंधित लेखाओं के साथ राज्य सरकार द्वारा निगम को अन्तरित कर दी जाएगी। नियत तारीख को तथा उसके पश्चात्, निगम, राज्य सरकार को अपवर्जित करके, इस बात के दायित्वाधीन होगा कि वह पेंशन, भविष्य निधि, उपदान या वैसी ही अन्य धनराशियों का, जो ऐसे कर्मचारियों को देय हों, समुचित समय पर संदाय उनकी सेवा-शर्तों के अनुसार करे।

(५) उपधारा (१) में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसे कर्मचारी को लागू नहीं होगी जो निगम का कर्मचारी न बनने या निगम का कर्मचारी न बने रहने का अपना आशय, नियत तारीख से दो मास के भीतर या बढ़ाए गए ऐसे समय के भीतर, जिसे राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, राज्य सरकार को दी गई लिखित सूचना द्वारा प्रज्ञापित कर देता है। जहां किसी कर्मचारी से ऐसी सूचना प्राप्त होती है, वहां—

(क) किसी स्थायी कर्मचारी की दशा में, उसे पेंशन, उपदान, भविष्य निधि संबंधी ऐसे फायदे तथा ऐसे अन्य फायदे, जोकि सरकारी सेवा से नियत तारीख को निवृत्त होने की दशा में उसे प्रोद्भूत होते, देकर सेवा-निवृत्त हो जाने दिया जाएगा;

(ख) किसी अस्थायी कर्मचारी की दशा में, राज्य सरकार के विद्यमान सेवा-नियमों के अनुसार उसे सूचना देकर या सूचना के बदले पारिश्रमिक देकर, उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी।

(६) पूर्वगामी उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) पशु चिकित्सा विभाग के नियोजन में के किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित हो या जिसे उसकी सेवा-समाप्ति संबंधी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति संबंधी कोई सूचना या आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख के पूर्व जारी किया जा चुका हो, निगम में स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा, और उक्त तारीख के पश्चात् ऐसे व्यक्ति के संबंध में ऐसी रीति में तथा ऐसे प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी जैसा कि राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे।

(ख) यदि राज्य सरकार के किसी कर्मचारी की सेवाएं निगम को उपधारा (१) के अधीन अन्तरित हो गई हों, तो ऐसे अन्तरण के पश्चात्, निगम इस बात के लिए सक्षम होगा कि वह ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध ऐ-नुशासनिक या अन्य कार्यवाही, जो वह उचित समझे, ऐसे कर्मचारी के उस समय के, जबकि वह राज्य सरकार की सेवा में था, किसी कार्य या कार्यलोप या आचरण या अभिलेख को ध्यान में रखते हुए करे।



निगम का समापन.

३०. निगम का समापन राज्य सरकार के आदेश से तथा ऐसी रीति में, जैसी रीति में, जैसी कि वह निदेशित करे, किया जायगा अन्यथा नहीं.

निदेशक की क्षति-पूति.

३१. (१) प्रत्येक निदेशक को उत्तरदायी ऐसी हानियों तथा व्ययों के लिये, जो उसके द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में या कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में उत्पन्न किए गए हों, इसका उत्तरदायी होने के लिये उत्तरदायी होगा जो उसकी क्षतिपूर्ति निगम द्वारा की जाएगी.

(२) कोई निदेशक किसी भी ऐसी हानि या ऐसे व्ययों के लिये उत्तरदायी नहीं होगा जो निगम की ओर से अजित की गई या ली गई किसी सम्पत्ति या प्रतिभूति के मूल्य की या उस पर के हक की अपर्याप्तता या कमी के कारण अथवा किसी अग्नि के या निगम के प्रति बाध्यताधीन किसी व्यक्ति के दिशाले या सदोष कार्य के कारण अथवा उसके संबंध में अपने पद के कर्तव्यों के निष्पादन में सद्भावपूर्वक की गई किसी बात के कारण निगम को उठाने पड़े हों.

निदेशकों की नियुक्ति में त्रुटि होने के कारण क्षति या अविधिमान्यता होना.

३२. (१) बोर्ड का या बोर्ड की किसी समिति का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि—

(क) यथास्थिति बोर्ड या समिति में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) निगम के निदेशक के रूप में या समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के नामनिर्देशन में कोई त्रुटि है; या

(ग) यथास्थिति बोर्ड या समिति की प्रक्रिया में कोई त्रुटि या अनियमितता है.

(२) निगम के निदेशक के रूप में या बोर्ड की किसी समिति के सदस्य के रूप में सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कार्य को केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझा जायगा कि वह व्यक्ति निदेशक या सदस्य होने के लिये निरहित था या यह कि उसकी नियुक्ति में कोई त्रुटि थी.

निगम के कर्मचारी-बुन्द लोक सेवक होंगे.

३३. निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को या ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसे निगम या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, जबकि वे इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध के अनुसार में कार्य कर रहे हों या जबकि उनका इस प्रकार कार्य करना तात्पर्यित हो, भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (१८६० का सं. ४५) की धारा २१ के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा.

इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही का संरक्षण.

३४. इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुई या संभाव्यतः होने वाली किसी हानि या नुकसान को लिये निगम के विरुद्ध या इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने के लिए निगम द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी.

विश्वस्तता तथा गोपनीयता की घोषणा.

३५. निगम का प्रत्येक निदेशक, संपरीक्षक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी या राज्य सरकार का कोई ऐसा कर्मचारी, जिसकी सेवाओं का उपयोग निगम द्वारा किया जाता है, अपना कर्तव्य ग्रहण करने के पूर्व विश्वस्तता तथा गोपनीयता की घोषणा विनियमों द्वारा विहित किए गए प्रारूप में करेगा.

शक्तियों का प्रत्यायोजन.

३६. बोर्ड इस अधिनियम के अधीन की अपनी शक्तियों तथा कृत्यों में से ऐसी शक्तियां तथा कृत्य, जिन्हें वह आवश्यक समझे, बोर्ड की किसी समिति को या निगम के अध्यक्ष या प्रमुख निदेशक या किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा.

निगम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति.

३७. (१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावशील करने के लिये ऐसे नियम बना सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों.

(२) इस धारा के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे.

317

३८. (१) निगम, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, उन समस्त विषयों के लिए, जिनके लिए इस अधिनियम विनियम बनाने की शक्ति दी गई है, के अधीन कोई नियम नहीं बनाए गए हैं और जिनके लिये उपबन्ध किया जाना, इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावशाली निगम की शक्ति करने के प्रयोजन से आवश्यक या समीचीन है, उपबन्ध करते हुए, ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों से असंगत न हों।

(२) विशिष्ट तथा पूर्णगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्न-लिखित विषयों के लिये उपबन्ध हो सकेंगे, अर्थात्:—

- (क) वह फीस तथा भत्ते जिनका संदाय निदेशकों को किया जा सकेगा;
- (ख) बोर्ड के या इस अधिनियम के अधीन गठित की गई किसी समिति के सम्मेलनों के समय तथा स्थान, और ऐसे सम्मेलनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत कामकाज के संपादन के लिये आवश्यक गणपूर्ति भी है;
- (ग) कार्यकारी समिति का गठन करने वाले निदेशकों की संख्या तथा वे कृत्य जिनका कि निर्वहन ऐसी समिति द्वारा किया जाएगा;
- (घ) वे कृत्य जिनका इस अधिनियम के अधीन निर्वहन किसी अन्य समिति द्वारा किया जा सकेगा;
- (ङ) वह फीस तथा भत्ते जिनका कि संदाय किसी समिति के उन सदस्यों को, जो निदेशकों से भिन्न हों, किया जा सकेगा;
- (च) वह रीति जिसमें प्रबन्ध निदेशक के आदेश के विरुद्ध अपील बोर्ड के अध्यक्ष को होगी;
- (छ) बोर्ड की शक्तियों तथा उसके कृत्यों का समितियों को या निगम के अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक तथा अन्य अधिकारियों को प्रत्यायोजन;
- (ज) निगम द्वारा बन्धपत्रों तथा डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों के पुरोधृत किए जाने तथा उनका मोचन किया जाने की रीति तथा निबन्धन;
- (झ) वह रीति तथा वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए निगम धन उधार ले सकेगा;
- (ञ) वह प्रारूप तथा रीति जिसमें निगम का तुलनपत्र और लेख तैयार किए जाएंगे तथा बनाए रखे जाएंगे;
- (ट) उन विवरणों, विवरणों तथा प्राक्कलनों के प्रारूप जिनका तैयार किया जाना इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित है;
- (ठ) निगम के कर्मचारियों के कर्तव्य तथा आचरण, उनके वेतन, भत्ते और उनकी सेवा की शर्तें;
- (ड) निगम के कर्मचारियों के लिये भविष्य निधि या अन्य प्रसुविधा निधियों (बेनिफिट फण्ड्स) की स्थापना तथा प्रबन्ध; और
- (ढ) साधारणतया निगम के कार्यकलापों के दृष्टांतपूर्ण संचालन के लिये।

३९. मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कृषि विकास निगम अध्यादेश, १९८२ (अध्यादेश १३ अक्टूबर १९८२) निरस्त।  
यह अध्यादेश निरस्त किया जाता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अक्टूबर 1982

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 1982

क्र. 2006-इक्कीस-अ (मा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अधिनियम, 1982 (क्रमांक 37 सन् 1982) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार;

दि. मा. भागवण, उपसचिव.

## MADHYA PRADESH ACT

No. 37 of 1982

### THE MADHYA PRADESH RAJYA PASHUDHAN EVAM KUKKUT VIKAS NIGAM ADHINIYAM, 1982.

#### TABLE OF CONTENTS

#### Sections :

#### CHAPTER I—PRELIMINARY

1. Short title and extent.

2. Definitions.

#### CHAPTER II—ESTABLISHMENT OF NIGAM, ITS CAPITAL AND MANAGEMENT

3. Establishment and incorporation of Madhya Pradesh Rajya Pashudhan Evam Kukkut Vikas Nigam,

4. Head Office of the Nigam.

5. Capital of Nigam.

#### CHAPTER III—MANAGEMENT OF THE NIGAM

6. Management.

7. Constitution of Board.

8. Disqualifications for being a Director of the Nigam.

9. Vacation of office by nominated directors.

10. Managing Director.

11. Casual vacancies in the office of the Managing Director.

12. Remuneration of directors.

13. Meeting of Board

14. Committees of the Board.

15. Member of Board or Committee thereof not to participate or vote in certain cases.

16. Managing Director to be appointing authority.

17. Condition of service of employees transferred to the Nigam from Government department.

**Sections :**

**CHAPTER IV—BUSINESS AND BORROWING OF THE NIGAM**

18. Business which the Nigam may transact.
19. Borrowing power of the Nigam.
20. Other sources of funds.

**CHAPTER V—EXECUTION OF PROJECTS**

21. Execution of works.

**CHAPTER VI—FINANCIAL ESTIMATES, FUNDS, ACCOUNTS AND AUDIT**

22. Submission of programme of activities and financial estimates.
23. Funds of the Nigam.
24. Preparation of balance sheets etc. of the Nigam.
25. Allocation of surplus profit.
26. Accounts and Audit.
27. Returns.

**CHAPTER VII—MISCELLANEOUS**

28. Power of State Government to give directions.
29. Transfer of Government employees to the Nigam.
30. Liquidation of the Nigam.
31. Indemnity of Director.
32. Defects in appointment of directors not to invalidate acts, etc.
33. Staff of the Nigam to be public servants.
34. Protection of action under the act.
35. Declaration of fidelity and secrecy.
36. Delegation of powers.
37. Power of the State Government to make rules.
38. Power of the Nigam to make regulations.
39. Repeal.

## MADHYA PRADESH ACT

No. 37 of 1982

THE MADHYA PRADESH RAJYA PASHUDHAN EVAM KUKKUT  
VIKAS NIGAM ADHINIYAM, 1982.

[Received the assent of the Governor on the 30th October 1982; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary)" dated the 30 October 1982.]

*An act to establish a Corporation for the execution of projects with a view to developing and providing for the scientific management of the livestock and poultry resources of the State and matters connected therewith.*

BE it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Thirty-third Year of the Republic of India as follows:—

## CHAPTER I—PRELIMINARY

Short title and  
extent.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Rajya Pashudhan Evam Kukkut Vikas Nigam Adhiniyam, 1982.

(2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "bank" means—

(i) a banking company as defined in the banking Regulation Act 1949 (No. 10 of 1949);

(ii) a scheduled bank as defined in the Reserve Bank of India Act, 1934 (II of 1934);

(iii) a financing bank as defined in the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961);

(b) "Board" means the Board of Directors of the Nigam constituted under section 7;

(c) "financing institution" means any statutory corporation or other body corporate established in India which as one of the objects of the financing of agriculture in India and which is notified by the State Government to be a financing institution for the purposes of this Act;

(d) "land" shall have the same meaning as assigned to that expression under the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);

(e) "Nigam" means the Madhya Pradesh Rajya Pashudhan Evam Kukkut Vikas Nigam established under this Act;

(f) "Project" means any project of or scheme for livestock and poultry development approved under section 22;

(g) "regulations" means regulations made by the Nigam under section 38;

(h) "year" means a period commencing from the 1st July and ending on the 30th June every year.



## CHAPTER II—ESTABLISHMENT OF NIGAM, ITS CAPITAL AND MANAGEMENT

3. (1) With effect from such date as the State Government may by notification appoint, there shall be established for the purposes of this Act a Nigam to be known as the Madhya Pradesh Rajya Pashudhan Evam Kukkut Vikash Nigam. Establishment and incorporation of the Madhya Pradesh Rajya Pashudhan Evam Kukkut Vikas Nigam.
- (2) The Nigam shall be a body corporate with the name aforesaid having perpetual succession and a common seal, with power, subject to provision of this Act, to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and shall by the said name sue and be sued.

4. The head office of the Nigam shall be at Bhopal.

Head office of the Nigam.

5. (1) The authorised capital of the Nigam shall be such sum not exceeding two crore of rupees as the State Government may, fix, from time to time. Capital of Nigam.

- (2) In respect of such sum as may be provided by the State Government as capital of the corporation, the State Government shall have power to impose such terms and conditions as it may deem fit.

## CHAPTER III—MANAGEMENT OF THE NIGAM

6. (1) The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Nigam shall vest in the Board of Directors which may exercise all such powers and do all such acts and things as may be exercised or done by the Nigam under this Act. Management.

- (2) The Board of Directors, in performing its functions shall act on business principles, regard being had to public interest, and shall be guided by such directions on questions of policy as may, from time to time, be given to it by the State Government.

7. (1) The Board of Directors of the Nigam shall consist of the Chairman to be nominated by the State Government and the following other directors namely :— Constitution of Board.

- (i) The Secretary to Government of Madhya Pradesh, Animal Husbandry Department and if there be no Secretary, then the Special Secretary of that Department, who shall be Vice-Chairman ;

- (ii) The Secretary to Government, Madhya Pradesh Finance Department or his nominee not below the rank of Deputy Secretary ;

- (iii) Director, Veterinary Services, Madhya Pradesh ;

- (iv) The Registrar of Co-operative Societies, Madhya Pradesh ;

- (v) A Managing Director to be appointed under section 10 :

- (vi) one Director to be nominated by the State Government to represent banks and financing institutions;
- (vii) one Director have special knowledge or practical experience in respect of livestock and poultry development to be nominated by the State Government;
- (viii) two Directors having practical experience in respect of livestock and poultry production and marketing to be nominated by the State Government;
- (ix) one representative of Scheduled Caste or Scheduled Tribes having practical experience in respect of matter relating to livestock and poultry to be nominated by the State Government;
- (x) one representative from the Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya to be appointed by State Government on the recommendation of the Vice-Chancellor.

(2) The Chairman or a nominated Director shall hold office during the pleasure of the authority nominating him but the term of his office shall not exceed three years from the date of notification of his nomination. The Chairman or a nominated Director may, however, resign his office at any time, by writing a letter under his hand to the State Government and the Chairman of the Board respectively and the resignation shall be effective from the date of its receipt.

(3) In the event of the death, resignation, or disqualification or removal of Chairman or a nominated director, the vacancy shall be filled up by nomination as soon as possible.

**Disqualification  
for being a Director  
of the Nigam**

8. (1) A person shall be disqualified for being nominated or appointed as, and for being a Director of the Nigam,—

- (a) if he is, or at any time has been adjudicated insolvent or has suspended payment of his debts or has compounded with his creditors; or
- (b) if he is of unsound mind stands so declared by a competent court; or
- (c) if he is, or has been convicted of any offence under the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (No. 59 of 1960), the Central Provinces and Berar Slaughter of Animals Act, 1915 (IV of 1915), or the Madhya Pradesh Agricultural Central Government or the State Government; or
- (d) if he is removed or dismissed from the service of the Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or the State Government; or
- (e) if he acts in any manner prejudicial to the interest of the Nigam or has any interest in any body, institution or organisation whose activities are prejudicial to the interest of the Nigam.

(2) If a Director of the Nigam becomes subject to any of the disqualifications mentioned in sub-section (1), he shall cease to be a Director of the Nigam with effect from the date of notification to this effect by the State Government.

9. (1) If a nominated Director,—

Vacation of  
office by nomi-  
nated Directors.

(a) becomes subject to any of the disqualifications mentioned in section 8; or

(b) is absent without leave of the Board for more than three consecutive meetings thereof without cause sufficient in the opinion of the State Government to exonerate his absence,

the State Government may declare that the said director shall be deemed to have vacated his office from the date of notification to this effect and thereupon his seat shall become vacant.

(2) A Director whose office has been declared vacant under sub-section (1) shall not be eligible for renomination to the Board as a Director for employment in the Nigam in any capacity.

10. (1) A Managing Director shall be appointed by the State Managing Director. Government and he shall—

(i) be a whole time officer of the Nigam;

(ii) exercise such powers and perform such duties as the Board may delegate or entrust to him;

(iii) receive such salary and allowances and be governed by such terms and conditions of service as the Nigam may, with the approval of the State Government, determine:

Provided that the first Managing Director shall receive such salary and allowances and be governed by such terms and conditions of service as the State Government may determine.

(2) The State Government may at any time remove the Managing Director from office without assigning any reason therefor.

11. If the Managing Director is by infirmity or otherwise, rendered incapable of carrying out his duties or is absent on leave or otherwise, in circumstances not involving the vacation of his appointment, the State Government may appoint another person to act in his place during his absence. Casual vacancies in the office of the Managing Director.

12. Directors, save as otherwise provided in section 10 shall be paid such fees and allowances as may be provided by regulations for attending the meeting of the Board or of any of its committees and for attending to any other work of the Nigam: Remuneration of Directors.

Provided that no fee shall be payable under this section to the Chairman, Managing Director or any other Director who is a Minister or holding an office of the State Government or of the Central Government.

13. (1) The Board shall meet at such times and places and shall observe such rules of procedure in regard to transaction of the Business Board at its meetings as may be provided by regulations: Meeting of

Provided that the Board shall meet at least once in every three months.

(2) The Chairman of the Board or, in his absence, any other director chosen by the directors present at the meeting shall preside over the meeting.



(3) All matters which come up before any meeting of the Board shall be decided by a majority of the votes of the Director present and voting and, in case of equality of votes, the person presiding of the meeting shall have a second or casting vote.

(4) In case the Board deems necessary to seek the advice or opinion of any person on any particular matter, the Board may invite such person to attend any meeting of the Board. Such an invitee shall have a right to participate in any discussion but shall have no right to vote at the meeting.

Committee of the Board.

14. (1) The Board may constitute one or more executive committees consisting of such number of Directors as may be provided by the regulations for discharging such functions as may be delegated to it by the Board.

(2) The Board may constitute such committees, whether consisting wholly of Directors or wholly of other persons, as it thinks fit, for such purposes, related to the activities of the Nigam as it may decide.

(3) The members of a committee other than the Directors of the Nigam shall be paid by the Nigam such fees and/or allowances for attending its meeting and for attending to any other work of the Nigam as may be provided by regulations.

Member of Board or committee thereof not to participate or vote in certain cases.

15. A Director of the Nigam or a member of a committee who has any direct or indirect pecuniary interest in any matter coming up for consideration at a meeting of the Board or a Committee thereof, shall disclose the nature of his interest at such meeting and the disclosure shall be recorded in the minutes of the Board or of the committee, as the case may be, and the director or member shall not take any part in any deliberation or decision of the Board or the committee with respect to that matter except to furnish such clarification as may be required of him.

Managing Director to be appointing authority.

16. The Managing Director, acting on behalf of the Nigam shall be deemed to be the appointing authority and shall exercise all powers of such an authority in respect of all staff employed by the Nigam. An appeal shall lie to the Chairman of the Board against the order of the Managing Director in this behalf, in such manner as may be provided by regulations.

Condition of service of employee transferred to the Nigam from Government Department.

17. (1) Subject to the provisions of section 29 any official transferred to the Nigam at the request of the Nigam permanently or temporarily by the State Government from any of their departments, shall enjoy all such privileges of gratuity, pensionary benefits and any other benefits to which that official would have been entitled had he continued to serve in his parent department in the State Government.

(2) An official specified in sub-section (1) shall, during the tenure of employment in the Nigam, be subject to disciplinary control of the Nigam.

#### CHAPTER IV—BUSINESS AND BORROWING OF THE NIGAM

Business which Nigam may transact.

18. The Principal business of the Nigam shall be production, procurement, collection, rearing and marketing of livestock and livestock products (except milk and milk products) poultry and poultry products and conservation, management and development of livestock and poultry so as to improve enrich and enhance livestock and poultry production in the State.

19. (1) The Nigam may with the previous approval of the State Government, issue and sell bonds and debentures carrying interest for the purpose of raising funds : <sup>Borrowing power of the Nigam.</sup>

Provided that without the approval of the State Government the total amount of bond and debentures issued and outstanding and of the other borrowing of the Nigam shall not at any time exceed four times the amount of the capital provided by the State Government under section 5.

(2) The Nigam may, for the purpose of carrying out its functions under this Act :—

(a) borrow money from the Central Government or the State Government and from any other authority or organisation or institution approved by the State Government, on such terms and conditions as may be agreed upon ; and

(b) accept from the Central Government, State Government, a Scheduled Bank or any person, deposits repayable after the expiry of a period which shall not be less than twelve months from the date of making the deposit and on such other terms as the Nigam may, with the prior approval of the State Government, fix.

(3) The bonds and debentures of the Nigam issued under sub-section (1) and the loans and deposits raised by the Nigam under clauses (a) and (b) of sub-section (2) may be guaranteed by the State Government as to the repayment of principal and the payment of interest at such rate as may be fixed by the State Government on the recommendation of the Board of Directors of the Nigam at the time the bonds or debentures are issued.

20. (1) The Nigam may receive remuneration for its services <sup>Other sources of</sup> including costs of works incurred by the Nigam under this Act and accept fund. gifts, grants, subsidies, donations or any benefactions from the State Government or from any person.

(2) The State Government may also transfer to the Nigam buildings, land, machinery or any other movable or immovable property for the use of the Nigam on such terms and conditions as the State Government may deem fit.

#### CHAPTER V—EXECUTION OF PROJECTS

21. The Nigam may execute the works itself or through any other <sup>Execution of works.</sup> agency.

#### CHAPTER VI—FINANCIAL ESTIMATES, FUNDS, ACCOUNTS AND AUDIT

22. (1) The Nigam shall, in respect of every year submit to the State Government a statement of programme of its activities together with annual financial statement showing therein the details of the estimated receipt and expenditure of the Nigam for that year. <sup>Submission of Programme of activities and financial estimate.</sup>

(2) The Nigam may, with the approval of the State Government revise or modify the statement and estimate referred to in sub-section (1)



(3) The Nigam shall submit each year to the State Government the programme of work and details of the project for different activities which are to be executed during the next year.

(4) The State Government may, either approve the project or may approve it with such modifications as it may consider necessary or may return it to the Nigam to modify the same or to prepare a fresh project in accordance with such directions as the State Government may deem appropriate.

#### Fund of the Nigam

23. (1) The Nigam shall have and maintain its own fund, and all receipts of the Nigam shall be carried thereto and all payment by the Nigam shall be made therefrom.

(2) The funds of the Nigam shall be applied by it for meeting all administrative expenses of the Nigam and for carrying out the purposes of this Act.

(3) The Nigam may deposit with any bank such sums as may be needed by it for its operations and the surplus may be invested in such manner as may be approved by the State Government.

#### Preparation of balance sheets etc. of the Nigam.

24. (1) The Board shall cause the books and accounts of the Nigam to be balanced and closed as on the thirtieth day of June each year.

(2) The balance sheet and accounts of the Nigam shall be prepared and maintained in such manner as may be prescribed by regulations.

#### Allocation of surplus profit.

25. (1) The Nigam shall establish a reserve fund to which shall be credited every year such portion of its annual net profits as the Nigam thinks fit.

(2) After making provision for such reserve fund and for bad and doubtful debts and all other matters which are usually provided for by companies registered and incorporated under the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956), the balance of its annual net profits shall be paid to the State Government.

#### Accounts and Audit

26. (1) The Nigam shall cause to be maintained proper books of accounts and such other books as the rules may require and shall prepare annual statement of accounts in the prescribed manner.

(2) The Nigam shall cause its accounts to be audited annually by such person as the State Government may direct.

(3) As soon as the accounts of the Nigam have been audited, the Nigam shall send a copy thereof together with a copy of the report of the auditor thereon to the State Government and shall cause the accounts to be published in the prescribed manner and place copies thereof on sale at a reasonable price.

(4) The Nigam shall comply with such directions as the State Government may after perusal of the report of the auditor think fit to issue.

#### Returns.

27. (1) The Nigam shall furnish to the State Government, from time to time, such returns as the State Government may require.

(2) The Nigam shall, in respect of each year, furnish to the State Government, within a period of three months from the date on which the annual accounts of the Nigam are closed, a copy of the balance sheet as on the close of that year, together with a profit and loss account for the year and a report on the working of the Nigam including its policy and programme during the year.

(3) The State Government shall, as soon as may be after the receipt of such report cause such report and the audit report received under section 26 to be laid on the table of Legislative Assembly.

## CHAPTER VII—MISCELLANEOUS

28. (1) In the discharge of its functions under this Act the Nigam shall be guided by such directions in matters of policy involving public interest as the State Government may give to it in writing, and if any question arises whether the direction relates to a matter of policy involving public interest, the decision of the State Government thereon shall be final.

Power of State government to give directions.

(2) Where the Nigam incurs any loss directly in consequence of carrying out the directions of the State Government under sub-section (1), the same shall be made good by the State Government.

29. (1) On and after the establishment of the Nigam the State Government may, from time to time, direct that the services of such of the existing officers and servants of the State Government who in its opinion, are rendered surplus to its requirements, shall stand terminated and their posts shall stand abolished, from such date as may be specified by it (hereinafter in this section referred to as the appointed date), and shall on that date (which may be different for different officers and servants) become the officers or servants of the Nigam.

Transfer of Government employees to the Nigam.

(2) Every permanent or temporary employees of the State Government in respect of whom a direction is issued under sub-section (1) shall, on and from the appointed date, be a permanent or temporary employees of the Nigam, as the case may be, against a permanent or temporary post, which shall stand created in the establishment of the Nigam with effect from the appointed date.

(3) Any officer or servant so transferred shall hold office under the Nigam by the same tenure, at the same remuneration and upon the same other conditions of service and with the same rights and privileges as to pension, gratuity, provident fund and other matters as would have been admissible to him on the appointed date if this Act had not come into force. Any service rendered by him under the State Government shall be deemed to be service rendered under the Nigam. He shall continue to serve under the Nigam until his employment is duly terminated or his remuneration or the conditions of service are duly revised or altered by the Nigam in pursuance of the law which for the time being governs his conditions of service:

Provided that, the conditions of service applicable immediately before the appointed date to the case of any such officer or servant shall not be varied to his disadvantage except with the previous approval of the State Government.

(4) The sums standing to the credit of the employees referred to in sub-section (1) in any pension, provident fund, gratuity or other like funds constituted for them shall be transferred by the State Government to the Nigam along with any accumulated interest due till the appointed date and with the accounts relating to such funds. On and after the appointed date, the Nigam shall, to the exclusion of the State Government be liable for payment of pension, provident fund, gratuity or other like sums as may be payable to such employees at the appropriate time in accordance with the conditions of their service.

(5) Nothing contained in sub-section (1) shall apply to any employees who by notice in writing given to the State Government within two months from the appointed date or such extended time as the State Government may, by general or special order, specify, intimate his intention of not becoming or continuing as a employee of the Nigam. Where such notice is received from any employee—

(a) in case of a permanent employee, he shall be allowed to retire giving him the benefit of pension, gratuity, provident fund and other benefits which may have accrued to him had he retired from the Government service on the appointed date;

(b) in case of a temporary employee, his service shall be terminated after giving him notice or remuneration in lieu of notice as per the existing service rules of the State Government.

(6) Notwithstanding anything contained in the forgoing sub-section—

(a) no person employed in the Veterinary Department against whom any disciplinary proceeding is pending or to whom any notice or order of termination of his service or compulsory retirement has been issued before the date of commencement of this Act shall be transferred to the Nigam, and such person may be dealt with after the said date in such manner and by such authority as the State Government may by general or special order specify in this behalf;

(b) if the services of any employees of the State Government stand transferred under sub-section (1) to the Nigam, the Nigam shall be competent after such transfer to take such disciplinary or other action as it thinks fit against such employee having regard to any act or omission or conduct or record of such employee while he was in service of the State Government.

Liquidation of the Nigam.

30. The Nigam shall not be placed in liquidation save by an order of the State Government and in such manner as it may direct.

Indemnity of director.

31. (1) Every Director shall be indemnified by the Nigam against all losses and expenses incurred by him, in or in relation to the discharge of his duties except such as are caused by his act or omission which is an offence under any law for the time being in force.

(2) A director shall not be responsible for any loss or expenses resulting to the Nigam from the insufficiency or deficiency of value of or title to any property or security acquired or taken on behalf of the Nigam or the insolvency or wrongful act of any debtor or any person under obligation to the Nigam or anything done in good faith in the execution of the duties of his office in relation thereto.



32. (1) No act or proceeding of the Board or of any committee of the Board shall be invalid merely by reason of—

Defects in appointment of directors not to invalidate acts etc.

- (a) any vacancy in or defect in the composition of the Board or committee, as the case may be; or
- (b) any defect in the nomination of any person acting as a Director of the Nigam or member of the Committee; or
- (c) any defect or irregularity in the procedure of the Board or Committee, as the case may be.

(2) No act done by any person acting in good faith as a director of the Nigam or as a member of a Committee of the Board shall be deemed to be invalid merely on the ground that he was disqualified to be a director or a member or that there was any defect in his appointment.

33. The Officers and employees of the Nigam or other person as may be authorised by the Nigam or the State Government when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (No. 45 of 1860).

Staff of the Nigam to be public servants.

34. No suit or other legal proceeding shall lie against the Nigam or any other person authorised by the Nigam to discharge any functions under this Act for any loss or damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done in the pursuance of this Act.

Protection of action under the Act.

35. Every director, auditor, officer or other employee of the Nigam or an employee of the State Government whose services are utilised by the Nigam, shall before entering upon his duties, make declaration of fidelity and secrecy in the form prescribed by regulations.

Declaration of fidelity and secrecy.

36. The Board may delegate to any committee of the Board or to the Chairman or Managing Director or any other officer of the Nigam such of its powers and functions under this Act, as it may deem necessary.

Delegation of powers.

37. (1) The State Government may make rules not inconsistent with the provisions of this Act to give effect to the provisions of this Act.

Power of the State Government to make rules.

(2) All rules made under this section shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

38. (1) The Nigam may, with the previous approval of the State Government make regulations not inconsistent with this Act and the rules made thereunder providing for all matters for which no rules have been framed under this Act and for which provision is necessary or expedient for the purpose of giving effect to the provisions of this Act.

Power of the Nigam to make regulations.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for the following matters, namely:—

- (a) the fees and allowances that may be paid to the directors;

- (b) the times places of the meeting of the Board or of any committee constituted under this Act and the procedure to be followed at such meeting including the quorum necessary for transaction of business;
- (c) the number of directors constituting the executive committee and the functions which such committee shall discharge;
- (d) the functions which any other committee may discharge under this Act;
- (e) the fees and allowances that may be paid to the member of a committee other than directors;
- (f) the manner in which appeal shall lie to the Chairman of the Board against the order of the Managing Director;
- (g) delegation of powers and functions of the Board to the committees or to the Chairman, the Managing Director and other officers of the Nigam;
- (h) the manner and terms of issue and redemption of bonds and debentures and other securities by the Nigam;
- (i) the manner and conditions subject to which the Nigam may borrow money;
- (j) the form and manner in which the balance sheet and accounts of the Nigam shall be prepared and maintained;
- (k) the form of returns, statements and estimates required to be prepared under this Act;
- (l) duties and conduct, salaries allowance and conditions of service of the employees of the Nigam;
- (m) establishment and management of provident fund or other benefit funds for employees of the Nigam; and
- (n) generally for the efficient conduct of the affairs of the Nigam.

Repeal.

39. The Madhya Pradesh Rajya Pashudhan Evam Kukkut Vikas Nigam Adhyadesh, 1982 (No. 13 of 1982) is hereby repealed.



मध्य प्रदेश के  
राज्यपाल के  
आदेश-नं.  
१२२/१९८४

पंजी क्रमांक भोपाल डिवी.३  
122 (एम. पी.)

25



ACU  
37/84

# मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, सोमवार, दिनांक 19 नवम्बर 1984--कार्तिक 28, शके 1906

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक १९ नवम्बर १९८४

२१११-एनटीसी-अ(आ).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक १७ नवम्बर १९८४ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार;  
एम. एम. दुबे, विशेष सचिव.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३७ सन् १९८४.

मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, १९८४.

[ दिनांक १७ नवम्बर १९८४ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १९ नवम्बर १९८४ को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]

मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अधिनियम, १९८२ को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम (संशोधन) अधिनियम १९८४ है.

धारा ७ के स्थान पर नवीन धारा का स्थापन.

२. मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अधिनियम, १९८२ (क्रमांक ३७ सन् १९८२); (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ७ के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

बोर्ड का गठन.

"७. (१) निगम का निदेशक-बोर्ड, अध्यक्ष तथा इतने अन्य शासकीय और अशासकीय निदेशकों से मिलकर बनेगा जितने कि राज्य सरकार नियुक्त करना ठीक समझे.

(२) शासकीय निदेशकों तथा अशासकीय निदेशकों का प्रतिनिधित्व ऐसे अनुपात में होगा जैसा कि राज्य सरकार अवधारित करे.

(३) राज्य सरकार, यदि वह ऐसा करना ठीक समझे, अन्य निदेशकों में से एक को बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकेगी.

(४) अशासकीय निदेशकों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:—

(क) बैंकों या वित्तादायी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक निदेशक;

(ख) पशुधन एवं कुक्कुट विकास के बारे में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाला एक निदेशक;

(ग) पशुधन एवं कुक्कुट उत्पादन तथा विपणन के बारे में व्यावहारिक अनुभव रखने वाले दो निदेशक;

(घ) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक निदेशक जिसे पशुधन एवं कुक्कुट संबंधी विषयों के बारे में व्यावहारिक अनुभव हो;

(ङ) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाला एक निदेशक.

(५) अध्यक्ष या कोई निदेशक, उसे नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा किन्तु उसके पद की अवधि उसकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष से अधिक की नहीं होगी. तथापि, अध्यक्ष या कोई निदेशक क्रमशः राज्य सरकार को तथा बोर्ड के अध्यक्ष को स्वहस्ताक्षरित पत्र भेजकर, अपना पद किसी भी समय त्याग सकेगा, और त्याग पत्र उसके प्राप्त होने की तारीख से प्रभावी होगा.

(६) अध्यक्ष या किसी निदेशक की मृत्यु हो जाने, उसके द्वारा पद त्याग कर दिए जाने या उसके निरहि्त हो जाने या उसे हटा दिए जाने की दशा में, वह रिक्ति नियुक्ति द्वारा यथा संभव शीघ्र भरी जाएगी."

धारा ८ को संशोधन. जाए.

३. मूल अधिनियम की धारा ८ की उपधारा (१) में, शब्द "नामानिर्दिष्ट किए जाने या" का लोप किया जाए.

धारा ९ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ९ की उपधारा (१) में, शब्द "नामानिर्दिष्ट" का लोप किया जाए.

निरसन.

५. मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम (संशोधन) अध्यादेश, १९८४ (क्रमांक १८ सन् १९८४) एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

भीषाल, दिनांक 19 नवम्बर 1984

क. २३३३७-इक्कीस-अ(प्रा.)-भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, १९८४ (क्रमांक ३७ सन् १९८४) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. एम. दुबे, विशेष सचिव

# MADHYA PRADESH ACT

No. 37 OF 1984

THE MADHYA PRADESH RAJYA PASHUDHAN EVAM KUKKUT VIKAS NIGAM (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1984.

[Received the assent of the Governor on the 17th November, 1984; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette" (Extraordinary), dated the 19th November, 1984.]

An Act to amend the Madhya Pradesh Rajya Pashudhan Evam Kukkut Vikas Nigam Adhiniyam, 1982.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Thirty-fifth Year of the Republic of India as follows :

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Rajya Pashudhan Evam Kukkut Short title. Vikas Nigam (Sanshodhan) Adhiniyam, 1984.
2. For Section 7 of the Madhya Pradesh Rajya Pashudhan Evam Kukkut Vikas Nigam Adhiniyam, 1982 (No. 37 of 1982), (hereinafter referred to as the Principal Act), the following section shall be substituted, namely:—
 

Substitution of new section for Section 7.

Constitution of Board.

  - "7. (1) The Board of Directors of the Nigam shall consist of a Chairman and such number of other official and non-official Directors as the State Government may think fit to appoint.
  - (2) The representation of official Directors and non-official Directors shall be in such proportion as the State Government may determine.
  - (3) The State Government may, if it so thinks fit, appoint one of the other Directors as the Vice-Chairman of the Board.
  - (4) The non-official Directors shall include,—
    - (a) one Director representing banks or financial institutions;
    - (b) one Director having special knowledge or practical experience in respect of livestock and poultry development;
    - (c) two Directors having practical experience in respect of livestock and poultry production and marketing;
    - (d) one Director representing Scheduled Castes or Scheduled Tribes having practical experience in respect of matters relating to livestock and poultry;
    - (e) one Director representing the Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya.
- (5) The Chairman or a Director shall hold office during the pleasure of the authority appointing him but the term of his office shall not exceed three years from the date of his appointment. The Chairman or a Director may, however, resign his office at any time by writing a letter under his hand to the State Government and the Chairman of the Board respectively and the resignation shall be effective from the date of its receipt.



(6) In the event of the death, resignation or disqualification or removal of Chairman or a Director, the vacancy shall be filled up by appointment as soon as possible.”.

Amendment of  
Section 8-

3. In sub-section (1) of Section 8 of the Principal Act, the words “nominated or” shall be omitted.

Amendment of  
Section 9.

4. In sub-section (1) of Section 9 of the Principal Act, the word “nominated” shall be omitted.

Repeal.

5. The Madhya Pradesh Rajya Pashudhan Evam Kukkut Vikas Nigam (Sanshodhan) Adhyadesh, 1984 (No. 18 of 1984) is hereby repealed.